शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार में
मध्यप्रदेश

समस्या

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा शिक्षकों को 9 जून से परीक्षाएं करानी होंगी

शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग में अफसरों के बीच तालमेल की बड़ी कमी सामने आई है। विभाग के उपसचिव ने शनिवार को आदेश जारी कर शिक्षकों के अवकाश की अवधि 30 जून तक बढ़ाई है। इसके बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साफ कहा है कि मंगलवार से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं में मास्टरों को ड्यूटी देनी होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह द्वारा शनिवार को जो आदेश जारी किया गया। उसके तहत शिक्षकों की अवकाश अवधि बढ़ाई गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शिक्षकों को 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि अप्रैल में जो आदेश जारी किया गया था उसके तहत 7 जून तक शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश थे। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए शिक्षकों के अवकाश की अवधि में वृद्धि की गई है। इसकी बाकायदा प्रति भी सभी जिलों में कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित की गई है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसर हुए चिंतित

इस आदेश को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी चिंता में पड़ गए हैं। मंडल में अधिकारियों का कहना है कि 9 जून से मुख्यमंत्री के निर्देश पर 12वीं के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं निर्धारित हुई है। विभाग को पूरी जानकारी होने के बाद भी 30 जून तक शिक्षकों की अवकाश अवधि बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस संदर्भ में मंडल के जनसंपर्क अधिकारी एसके चौरसिया ने दूरभाष पर बताया है कि 9 जून से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं में शिक्षकों को ड्यूटी करनी होगी। पहले से ही प्राचार्य और व्याख्याताओं को केंद्र अध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक निर्धारित समय पर ड्यूटी करने पहुंचेंगे।

छुट्टी के आदेश से शिक्षक भी पड़े असमंजस में

अवकाश संबंधी आदेश जारी होने से शिक्षक भी असमंजस में पड़ गए हैं। मध्य प्रदेश समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दुबे ने कहा कि विभाग में अधिकारियों के बीच कोई तालमेल नहीं है। आदेश जारी करने के पूर्व मंडल से मशविरा जरूरी था। अब यदि परीक्षा में शिक्षकों को बुलाया जाएगा तो वह आदेश का हवाला देते हुए इसका विरोध करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। उन्होंने तो यही मांग की है कि परीक्षाएं बीमारी के संक्रमण को देखते हुए तत्काल निरस्त होना चाहिए। इधर क्लास 3 में शिक्षक समिति के अध्यक्ष अरविंद भूषण श्रीवास्तव का कहना है कि शिक्षा विभाग में अफसरों की आपसी राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है। यही कारण है कि शिक्षक जहां प्रताड़ित हो रहे हैं वही बच्चों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है।

प्रदेश के स्कूलों में 30 जून तक छुट्टी, ऑनलाइन होंगी कक्षाएं

भोपाल, संवाददाता

चीनी वायरस के संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए पहले सरकार ने 7 जून तक स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी। लेकिन प्रदेश में वायरस के संक्रमण की गति को देखते हुए इन छुट्टियों को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। विभाग ने इस बाबत जारी नोटिस में कहा है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पहले 7 जून तक अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। शनिवार को जारी किए गए इस आदेश में विभाग ने कहा है कि आम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में 7 जून तक की अवकाश अवधि को संशोधित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी स्कूलों में 30 जून तक रहेगा अवकाश

भोपाल, (शप्र)। शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस एवं उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए 30 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां विभागीय आदेश के अनुसार जारी रखी जा सकेंगी। पूर्व में अवकाश की तिथि 7 जून तक घोषित थी। जिसे अब बढ़ाकर तीस जून तक कर दिया गया है। तीस जून के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने के संबंध शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

जुलाई से स्कूल खेलने के पक्ष में नहीं ज्यादातर राज्य सरकारें

ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर ज्यादा जोर देने की बात कही

जेएनएन, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित ज्यादातर राज्य जुलाई में स्कूलों को खोलने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। ज्यादातर राज्यों में स्कूलों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। कोरोना संक्रमण और संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन्हें खाली करना संभव नहीं है। वहीं, कई राज्यों को केंद्र की गाइडलाइन का भी इंतजार है। दो दिन बाद राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। हालांकि, अंतिम निर्णय पैरेंट्स से पूछने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर ज्यादा जोर है। राजस्थान में फिलहाल 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। सरकार की ओर से अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई तैयारी नहीं है। स्कूलों को लेकर ना ही कोई कमेटी बनाई गई है। राज्य सरकार इस मामले में केंद्र से आने वाली गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। वहीं, सरकार का कहना है कि स्कूल खोलने को जुलाई में कहा गया है। लेकिन, अभी कोई तारीख नहीं तय की गई है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र भी स्कूल खोलने की रणनीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि दूरवर्ती इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी और संक्रमण नहीं है, वहां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्कूलों को खोला जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई में स्कूल खेलने से साफ इनकार कर दिया है।

केंद्र से गाइडलाइन मिलने और पैरेंट्स से पूछने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा

प्राचार्य के हस्ताक्षर व सील के बिना भी मान्य होंगे प्रवेश-पत्र

9 जून से दो पालियों में शुरू होगी परीक्षा

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थगित बारहवीं परीक्षाओं के नए प्रवेश पत्र प्राचार्य के हस्ताक्षर व सील के बिना भी मान्य होंगे। माशिमं ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए है। माशिमं की बारहवीं की स्थगित परीक्षा 9 जून से दो पालियों में शुरू होगी। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बारहवीं की स्थगित परीक्षा के शेष विषयों की परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र जारी किए है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के संशोधित तिथि एवं जिला परिवर्तन व केंद्र परिवर्तन से संबंधित प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए है। संबंधित संस्था या छात्र एमपी आनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। आनलाइन उपलब्ध कराए प्रवेश पत्रों में संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा का प्रावधान है। मंडल द्वारा छात्रहित में निर्णय लिया गया है कि यदि कोई छात्र जिला परिवर्तन के कारण या अन्य कारण से प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर कराने में असमर्थ है, तो संबंधित छात्र को संबंधित संस्था के प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी परीक्षार्थी उक्त कारण से परीक्षा से वंचित न हो।

9वीं-11वीं के विद्यार्थी करा सकेंगे पुनर्गणना

भोपाल। अब प्रदेशभर में अपने रिजल्ट से असुंष्ट विद्यार्थी पुनर्गणना के आवेदन कर सकेंगे। 30 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी को उनके आवेदन का निराकरण करना होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री कियावत ने शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया था, जिस कारण वार्षिक परीक्षा परिणाम से संतुष्ट न होने वाले विद्यार्थी को पुनर्गणना का मौका दें।

नवीन शिक्षण सत्र से पूरी तरह स्कूलों में दिखेगा परिवर्तन

प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य पर रहेगी शिक्षकों की नजर, सफाई के होंगे बेहतर इंतजाम

भोपाल (आरएनएन)। नवीन शिक्षण सत्र को प्रारंभ करने के लिए सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे स्कूल शिक्षा विभाग ने कई बदलाव करने की तैयारी की है। भोपाल में अधिकारियों का कहना है कि शालाओं में इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने की भी शिक्षकों के कंधों पर महिती जवाबदारी होगी। राजधानी में वैसे तो नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। पर अभी शासन के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है। मैदानी अधिकारियों का कहना है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी को देखते हुए इस बार प्रत्येक शाला में सुरक्षा उपायों को जुटाना एक चुनौती है लेकिन हम पूरी तरह गंभीर है। भारत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हर स्कूल में सेनीटाइज की व्यवस्था होगी। पानी की टंकियों की नियमित रूप से सफाई होगी। ताकि बच्चे साफ पानी पी सके। शौचालयों की हर दिन सफाई करवाई जाएगी। प्रत्येक शाला में बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर बच्चे के हाथ में रुमाल होगा उसे मास्क लगाकर स्कूल जाना होगा। अगर बच्चे के पास यह व्यवस्था नहीं है स्कूल प्रबंधन उसकी पूर्ति करेगा।

स्कूलों में स्वच्छ वातावरण रहेगा: श्रीवास्तव

डीपीसी प्रभाकर श्रीवास्तव का कहना है कि स्कूलों में स्वच्छ माहौल बनाया जाएगा। हर कक्षा में शिक्षक बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने का ज्ञान देगा। बच्चों को बताया जाएगा कि किस प्रकार वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर पढ़ाई करें। डीपीसी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक स्कूल में सेनीटाइज की व्यवस्था रखी जाएगी। जहां नियम से बच्चों के हाथ साफकराए जाएंगे। बेहतर साफसफाई भी हर शाला में होगी। उन्होंने कहा है कि बच्चों को भयमुक्त बनाने के लिए भी स्कूलों में उनकी काउंसलिंग की जाएगी।

अधिकारियों को जो निर्देश उसी के अनुसार कार्य

फंदा ग्रामीण में बीआरसीसी रविंद्र जैन का कहना है कि अधिकारियों के जो निर्देश होंगे उसी के अनुसार शालाओं में काम होगा। उन्होंने बताया कि शुरू से ही फंदा ग्रामीण में कैलेंडर के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण किया जाता रहा है। आगे भी यह क्रम यथावत जारी रखा जाएगा। रविंद्र जैन का कहना है कि स्कूलों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा वहीं प्रत्येक बच्चे को मास्क और सैनिटाइज उपलब्ध कराने के भी पूरे प्रयास होंगे। उन्होंने बताया है कि किताबी ज्ञान के साथ.साथ बच्चों को कोरो ना के प्रति जागरूक करना भी एक बड़ी चुनौती है लेकिन हम इस चुनौती से पूरी तरह लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों से समन्वय बनाकर काम किया जाएगा।

पुलिस को पदोन्नति पदनाम मिला तो 17000 वन कर्मचारी हुए नाराज

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति के आदेश जारी करने पर वन सेवकों ने सरकार पर नाराजगी जताई है। जंगल कर्मचारियों का कहना है कि जब पुलिस को यह लाभ मिला तो आखिर उनके साथ अन्याय क्यों?। इस संबंध में वन विभाग के कर्मचारियों ने मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के पार्क में बैठक की इसके बाद सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री आमोद तिवारी ने बताया कि राज्य में 12000 नाकेदार एवं 4 हजार वन क्षेत्रपाल है। इन सभी सेवकों ने अपने 12 साल की सेवा पूर्ण कर ली है। नियम यही है कि इतनी सेवा करने के बाद कर्मचारी को मान सेवा के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। तिवारी का आरोप है कि पुलिस विभाग में प्रमोशन का यह लाभ दे दिया गया है लेकिन वन विभाग में कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है जबकि इन्हें समय मान पहले से मिल रहा है। सिर्फ पदोन्नति पदनाम चाहिए। उसके बाद भी विभाग द्वारा इस गंभीर मामले में आनाकानी की जा रही है। तिवारी का कहना है कि कोरोना जैसी भीषण आपदा में कर्मचारी जंगलों की रखवाली कर रहे हैं। इस दौरान कई कर्मचारियों पर जानवरों के हमले भी हुए हैं। दो कर्मचारी की तो मौत भी हो गई है। उसके बाद भी मानवीय रवैया नहीं अपनाया जा रहा है।

जंगल कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर रही है अन्याय

चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में आ रहे बच्चों के फोन

ऑनलाइन क्लास से सभी बच्चे कंफर्टेबल नहीं

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्कूलों के बंद होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी हैं। ऐसे में बच्चे दूसरी कशमकश में फंसे हैं और चाइल्ड लाइन फोन कर अपनी परेशानी सांझा करने के साथ ही स्कूल खुलने संबंधी जानकारी मांग रहे हैं। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर बीते एक माह में 11 बच्चों ने फोन कर जानकारी मांगी कि क्या सचमुच इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे। वहीं बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आने वाली परेशानी भी शेयर की है। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अर्चना सहाय ने बताया कि बच्चे घर में रहते हुए अब पैनिक होने लगे हैं। अब स्कूल नहीं भेजे जाने की बात घर में होने के कारण बच्चे उससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी ओर ऑनलाइन क्लासेस का दबाव और तनाव भी बच्चों पर नजर आने लगा है। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे।

खास बातें

- एक माह में 11 बच्चों ने फोन कर मांगी जानकारी क्या इस साल नहीं खुलेंगे स्कूल
- ऑनलाइन क्लासेस का दबाव और तनाव भी बच्चों पर नजर आने लगा

एक मोबाइल की व्यवस्था करवा दो

12 वर्षीय बच्चे ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर कहा कि आठ जून से ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। मम्मी-पापा अपना-अपना फोन लेकर ऑफिस जाते हैं, मैं क्लास कैसे अटैंड करूं, आप एक मोबाइल की व्यवस्था करवा दो।

बच्चों को मम्मी-पापा नहीं देते मोबाइल

बच्चे ने यह भी बताया कि ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल देने की बात पर मम्मी-पापा की लड़ाई भी होती है और दोनों में से कोई भी अपना मोबाइल उसे देकर जाना नहीं चाहता। एक 8 साल के बच्चे ने फोन पर कहा कि वह घर में रह-रह कर परेशान हो गया है। मम्मी-पापा ना कॉलोनी में फ्रेंड्स के साथ खेलने देते हैं और ना ही कहीं घुमाने ले जाते हैं। उसने कहा कि स्कूल में उसका न्यू सेक्शन बन चुका है और वह अपने नए दोस्तों से मिलना चाहता है।

बच्चे ने कहा-टीचर को बर्थडे विश करना है

छह साल के एक बच्चे ने चाइल्ड लाइन से कहा कि उसकी फेवरेट टीचर से उसे 20 जून को मिलवा दे या उनका नंबर पता करके दे दे। बच्चे की बात पर चाइल्ड लाइन सदस्य ने पूछा कि आपको नंबर क्यों चाहिए तो बच्चे ने कहा स्कूल टीचर ने अपना नंबर नहीं दिया है और मुझे 20 जून को उन्हें बर्थडे विश करना है। वहीं एक 10 साल की बच्ची ने चाइल्ड लाइन से कहा कि दादी कहती हैं पूरे साल स्कूल नहीं लगेगा तो घर बैठकर इतने साल का सिखा सब भूल जाओगी। बच्ची ने पूछा कि क्या इस साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी।

केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें डीए के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी।

ऑनलाइन होगी पढ़ाई, बच्चों को मोबाइल खरीदकर दो

निजी स्कूलों ने पालकों को भेजे मैसेज, ई-बुक व एकमुश्त फीस भरने की शिकायत की

भास्कर संवाददाता | खरगोन

पालकों ने शनिवार को प्रायवेट स्कूलों की एसडीएम अभिषेक गेहलोत को शिकायत कर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है निजी स्कूल संचालक ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर महंगे मोबाइल खरीदने, एकमुश्त फीस जमा कराने व ऑनलाइन बुक की राशि जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं।

शिकायत के मुताबिक पालकों को 15 जून से ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के लिए इंटरनेट डेटा के साथ एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने व ई-बुक की राशि जमा कराने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। ज्यादातर पालक लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में एनसीआरटीई का ही पाठ्यक्रम चलाने के आदेश हैं। इसके अलावा कई तरह की निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने को भी कहा जा रहा है। इस दौरान सुबोध जोशी, रजत डंडीर, सौरभ निखोरिया, रजत शर्मा, दीपक रघुवंशी, आशीष परसाई, अक्षय खोड़े, संजय पाराशर, रविंद्र निखोरिया आदि थे। पालकों की शिकायत पर एसडीएम ने मामले को दिखवाकर उचित कार्रवाई करने को कहा है।

निजी स्कूलों की शिकायत करने पहुंचे।

यह है पालकों की दो मांग

1. एकमुश्त फीस का दबाव नहीं बनाए। प्रतिमाह ली जा रही फीस में 50 प्रतिशत कटौती।

2. निजी प्रकाशकों की बुक खरीदी का दबाव बनाकर स्कूलों में कमीशनखोरी पर रोक।

पालक बोले- काम बंद, नया मोबाइल खरीदना मुश्किल

- मुनीम आनंद महाजन ने बताया कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन से निजी कामकाज पूरी तरह से बंद है। घर में एक ही मोबाइल है। दो बेटियों को एकसाथ ऑनलाइन कक्षा चलेगी। एकसाथ दो नए मोबाइल खरीदकर दिला पाने की क्षमता नहीं है।

- पंडित दीपक भट्ट ने कहा काम पर जाता हूं। नहुष पहली में है। पत्नी कम पढ़ी-लिखी हैं। उन्हें ऑनलाइन मोबाइल चलाने के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है। नया मोबाइल खरीदने व ऑनलाइन न पढ़ा पाने की बात बताई, लेकिन उनका कहना है यह आपकी समस्या है।

कंटेनमेंट एरिया के विद्यार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र

थर्मल स्क्रीनिंग होगी, बीमार मिला तो स्वास्थ्य टीम भर्ती करेगी

खरगोन | माध्यमिक शिक्षा मंडल की 9 जून से हो रही 12वीं की शेष परीक्षा में कंटेनमेंट एरिया के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। विद्यार्थी अपना परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाकर बाहर आ सकेंगे। इस संबंध में मंडल ने जिला व पुलिस प्रशासन को समन्वय के साथ कार्रवाई को कहा है ताकि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित न हो। जिला शिक्षा अधिकारी केके डोंगरे ने बताया जिले में 90 केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनेटाईजर सहित जरूरी सामान रहेगा। सामान की खरीदी की जा रही है। केंद्र पर जनशिक्षक, स्वास्थ्य व राजस्व कर्मचारियों की एक टीम तैनात रहेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही केंद्र में परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

प्रत्येक केंद्र में जांच थर्मल स्क्रीनिंग में तापमान अधिक पाए जाने पर छात्र को आइसोलेशन कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो क्षेत्र के बीएमओ के माध्यम से उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा में शामिल सभी शिक्षक, कर्मचारी व अन्य अमले की भी नियमित स्क्रीनिंग होगी।

फर्जी कॉल के झांसे में न आएं • एसपी बोले- लोग सतर्क रहें, शेयर न करें बैंकिंग डेटा, दसवीं के परिक्षार्थियों का मामला

सीबीएसई परीक्षार्थियों का डेटा लीक, पास कराने के आ रहे फोन

भास्कर संवाददाता | खरगोन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की हाई स्कूल की परीक्षा 26 फरवरी से 18 मार्च के बीच में हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद विद्यार्थी परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच परीक्षार्थियों के डेटा लीक हो गए हैं। खरगोन शहर में पिछले 3-4 दिनों में 60 से ज्यादा पालकों के मोबाइल पर उनके नाम, बच्चे का नाम व स्कूल के नाम के साथ फोन आ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सीबीएसई से बोल रहा हूं। आपका बच्चा एक विषय में फेल हो रहा है। ऑनलाइन खाते में 12 हजार 500 रुपए राशि जमा करा देंगे तो वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा।

पुलिस ने सतर्कता जारी की।

12 हजार 500 रुपए में 85 अंक चढ़ा देंगे

फर्जी कॉल में कहा जा रहा है कि यदि 12 हजार 500 रुपए खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करना होंगे। आधी रकम जमा करते ही अंकसूची आ जाएगी। बाकी की रकम डालते ही फेल विषय को अच्छे अंकों से पास करके पीडीएफ फाईल भेज दी जाएगी। 65 नंबर अंकसूची में चढ़ाने के 10 हजार व 85 अंक के 12 हजार 500 रुपए खाते में जमा कराने को कहा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि हाई स्कूल का 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा। जल्दी निर्णय लें।

जिला शिक्षा अधिकारी केके डोंगरे का कहना है पालकों से जानकारी सामने आई। मामले की पुलिस को शिकायत की गई है। किसी भी पालक के पास फर्जी कॉल आए तो उसकी डिटेल के साथ शिकायत दर्ज कराएं। मामले की कुछ पालकों ने एसपी सुनील पांडेय से शिकायत की है। एसपी ने टीआई जगदीश गोयल को जांच करने को कहा है। साथ ही पालकों को सतर्क रहने व बैंकिंग डेटा शेयर न करने का आग्रह किया है।

इन दो केस से समझिए ये मामला

4 बच्चों को आए कॉल

शिक्षक हरिओम गुप्ता ने बताया हमारे संस्थान से 4 बच्चों को कॉल आए। हमने सभी विद्यार्थियों को इसे फर्जी काल बताकर किसी भी तरह से ऑनलाइन ट्रांसफर न करने को कहा है। सोशल मीडिया में बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं।

अंक चढ़ाने के मांगे रु.

पालक प्रकाश भावसार ने कहा बेटे, मेरे व स्कूल के नाम से फोन आया था। 10वीं सोशल साइंस में बच्चे के फेल होने पर 10 हजार रु. में 65 व 12500 रु. में 85 अंक तक चढ़ाने को कहा। पहले आधी राशि ट्रांसफर करने को कहा। शिकायत की है।

लॉकडाउन में फर्जी कॉल आने की सूचनाएं मिल रही हैं। लोगों को सतर्क रहने संबंधी मैसेज जारी किया है। जिसमें बैंकिंग संबंधी डेटा का किसी से भी शेयर न करने को कहा गया है। शिकायतों की जांच करा रहे हैं।

- सुनील पांडेय, एसपी खरगोन

प्रवेश पत्र दिखाकर कंटेनमेंट से बाहर आ सकेंगे परीक्षार्थी

12वीं की परीक्षा 9 जून से, दूसरे जिले से आए विद्यार्थी भी यहीं दे सकेंगे परीक्षा

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थगित 12वीं की परीक्षाओं को 9 जून से कराने की तैयारी की जा रही है। इधर कंटेनमेंट एरिया के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर जाने को लेकर असमंजस में हैं। अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थी मार्च में जारी हुए प्रवेश पत्र या प्रवेश पत्र की सॉफ्ट कॉपी दिखा कर भी परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे।

मंडल ने पहली बार यह व्यवस्था भी की है कि जो विद्यार्थी लॉकडाउन की वजह से अन्य जिलों में चले गए हैं, वे वहीं पर ही परीक्षा दे सकेंगे। इधर शहर में कई इलाके अभी भी कंटेनमेंट हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे का कहना है कि विद्यार्थियों को मार्च से जो प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, उसके आधार पर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर जा सकेंगे और परीक्षा में बैठ सकेंगे। इधर परीक्षा की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों ने सभी केंद्र अध्यक्षों को निर्देश भी दिए हैं। परीक्षाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी नाहटे ने 2 सत्रों में 90 केन्द्राध्यक्षो की मीटिंग ली। सहायक संचालक अभय तोमर ने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी का थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर देखा जाएगा। परीक्षार्थियों को अपने साथ पानी की बोतल एवं मास्क लाने के लिए कहा गया है।

छात्रों को प्राचार्य वितरित करेंगे प्रवेश-पत्र

डीईओ ने किया निर्देशित परिवर्तित केंद्र के छात्रों को न हो परेशानी

जागरण, रीवा। कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए जारी संशोधित प्रवेश पत्र प्राचार्य द्वारा वितरित किए जायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बाबत शनिवार को सूचना जारी की है। पत्र में डीईओ ने बताया कि जिले में चार परीक्षा केंद्र बदले गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए कंटेनमेंट जोन बनने के कारण उक्त केंद्रों को बदलना पड़ा है। इस बाबत जिला कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मार्च 2020 में 12वीं परीक्षा के दौरान शासकीय विद्यालय गोड़हर परीक्षा केंद्र बना रहा। इसी तरह ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, कटरा विद्यालय व खजुहा विद्यालय परीक्षा केंद्र बने थे, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। बताया गया कि जिन छात्रों का केंद्र गोड़हर विद्यालय में रहा, उनके लिए अब उमादत्त विद्यालय ढेकहा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसी प्रकार ज्ञानोदय विद्यालय के स्थान पर सेंट्रल एकेडमी स्कूल, कटरा विद्यालय के बदले शासकीय हाइस्कूल जमुई तथा खजुहा विद्यालय का केंद्र परिवर्तित कर लक्ष्मणपुर विद्यालय को नया केंद्र बनाया गया है। डीईओ ने पूर्व के केंद्रों में शामिल होने वाले सभी छात्रों को केंद्र परिवर्तन की सूचना विशेष रूप से देने के लिए कहा है, जिसका उल्लेख छात्रों के नवीन प्रवेश पत्र में भी है।

गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं हमेशा की तरह नियत समय गत मार्च माह में प्रारम्भ हो चुकी थी परंतु कोरोना वायरस से फैल रही महामारी की रोकथाम हेतु तब परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अब 10वीं के छात्रों को उत्तीर्ण करने की घोषणा माशिमं ने कर दी है। जबकि 12वीं के छात्रों की शेष विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम माशिमं ने घोषित किया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं के शेष विषयों की परीक्षा 9 से 16 जून के बीच होगी। इस परीक्षा में जिले के 24 हजार 273 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

माशिमं ने छात्रों को राहत देने के लिए कहा

इस परीक्षा के लिए जारी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में प्राचार्य के हस्ताक्षर व पदमुद्रा की बाध्यता नहीं होगी। इस बाबत माशिमं सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी पत्र में उल्लेख है कि संशोधित तिथि में परीक्षा हेतु, जिला परिवर्तन, केंद्र परिवर्तन के प्रवेश पत्र जिन छात्रों को ऑनलाइन जारी किए गए हैं, उनमें संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर व पदमुद्रा का प्रावधान है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि जो छात्र ऑनलाइन प्राप्त प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर व पदमुद्रा कराने में असमर्थ हैं, उन्हें इस कार्य के लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा बाध्य न किया जाये तथा छात्रों को परीक्षा में सम्मलित करा लिया जाये।

1 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र

माशिमं ने कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर 1 घंटे पूर्व उपस्थित होने के लिए कहा है। ताकि परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्कीनिंग की जा सके। आगामी परीक्षाएं दो पाली में होंगी। पहली पाली की परीक्षा प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। बताया गया कि प्रथम पाली के विद्यार्थियों को प्रातः 8 बजे तक तथा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को दोपहर 1 बजे तक केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8.45 एवं दोपहर 1.45 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर-पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न-पत्र दिये जायेंगे। हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम दृष्टिहीन, मूक, बधिर (दिव्यांग), नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षाएं अपरान्ह 2 से 5 बजे तक होंगी।

मास्क लगाएं व सफाई का ध्यान रखें छात्र

बताया गया कि परीक्षा केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक और मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढंक कर रखना और फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा उपरांत छात्र समूह न बनायें। प्रयास करें कि अकेले या अपने परिजनों के साथ तुरंत घर पहुंचे और हाथ धुलाई जैसी अन्य सफाई का विशेष ध्यान रखें।

हजारों अध्यापक राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्ति से वंचित

जवा ब्यूरो। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलो मे कार्यरत अध्यापको का राज्य स्कूल शिक्षा सेवा अंतर्गत नवीन शिक्षक संबर्ग मे नियक्ति किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। जिसके तहत सैकड़ो संविदा शिक्षक से अध्यापक बने शिक्षक आज भी राज्य स्कूल शिक्षा सेवा मे नियुक्ति से बंचित होने के कारण शासन द्वारा दिये जाने वाले वेतन व अन्य लाभ उन्हे नही मिल पा रहा है।उक्ताशय की जानकारी देते हुए पुष्पेंद्र द्विवेदी संभागीय प्रवक्ता आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जवा ने बताया कि जिले मे हमारे हजारो अध्यापक साथी जो संविदा शिक्षक से अध्यापक संबर्ग मे व शेष बचे अध्यापक राज्य स्कूल शिक्षा सेवा मे नियुक्ति से वंचित है,जिसमे अकेले जवा के लगभग चार सैकड़ा सहायक अध्यापक, अध्यापक ,जिन्हे विना किसी ठोस वजह के लोकायुक्त प्रकरण दर्ज कर या लांवित करके राज्य शिक्षा सेवा मे नियुक्ति से वंचित रखा गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार सभी अध्यापको की फ़ाइल की पूर्ति कर संकुलो से आनलाइन जिला भेजी जा चुकी है, तथा निर्धारित फर्मेट मे एक्सल सीट मे जानकारी जमा करा दी गयी है। फिर भी आज तक उन सभी अध्यापको का संविलियन राज्य शिक्षा सेवा के नवीन संबर्ग मे नियुक्ति आदेश जारी नही हो सके है।जिनकी फ़ाइल जाना शेष है, उनके लिए जिले से पृथक से आदेश जारी कर जानकारी संकुलो से मांगी जा सकती है। जिले के कई अध्यापक/ नवीन संबर्ग जिनकी सेवाएं 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनके क्रमोन्नति की कार्यवाही भी लांवित है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला रीवा के राजेश सिंह प्रांतीय संगठन मंत्री रमेश प्रताप सिंह संभागीय अध्यक्ष रूपेश पांडेय, संजय सिंह, रमाकांत मिश्रा, बालेंद्रशेखर द्विवेदी, चक्रपाणि सिंह, पुष्पराज गिरि, मनीष चदानन, रजनीश चतुर्वेदी, प्रमोद चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा, अशोक पांडेय, अतुल दुबे आदि ने संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग रीवा व जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शेष बचे अध्यापकों को नवीन संबर्ग मे नियुक्ति व क्रमोन्नति को शेष बचे अध्यापको के आदेश जारी कराये जाने की मांग की है।

फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों की सेवा बहाली हमारी प्राथमिकता

नसं, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतिथि विद्वानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। हम जल्द फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों की सेवा बहाली व नियमितीकरण पर निर्णय लेंगे। यह बात कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने अपने गृह जिले उमरिया के प्रवास पर उपस्थित हुए अतिथि विद्वानों के एक प्रतिनिधिमंडल से कहीं। उमरिया में फॉलेन आउट अतिथि विद्वान डॉ राजू रैदास के नेतृत्व में अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा की ओर से मंत्री मीना सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में डॉ मंसूर अली, डॉ जेपीएस चौहान एवं रामायण वर्मा शामिल थे। ज्ञापन में अतिथि विद्वानों की ओर से कहा गया है कि कोरोना संकट ने अतिथिविद्वानों की आर्थिक स्थिति को जर्जर कर दिया है। जहां प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में मज़दूरों और किसानों की भरपूर मदद कर रही है। कोरोनाकाल के दौरान सभी फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों को भी न्यूनतम मानदेय भुगतान किया जाए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में रहे।

परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर परिधि में लागू रहेगी धारा 144

नौ जून से प्रारंभ होंगी हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएं

मुरैना, ब्यूरो

माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की शेष बची परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दो पालियों में संपन्न कराई जा रही हैं। इन परीक्षाओं के लिये जिले में 66 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 8 संवेदनशील एवं 37 अतिसंवेदनशील चिन्हित है। परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी 66 परीक्षा केंद्रों पर स्थाई पैनल नियुक्त किए गए हैं तथा मुख्य विषय गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के दिनांक में संवेदनशील अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं तथा जिला स्तरीय एवं अनुविभाग स्तर पर उड़नदस्तों का भी गठन किया गया है।

जिलाधीश श्रीमती प्रियंका दास ने बताया कि जिले में 66 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। परीक्षा केन्द्रों पर एवं परीक्षा केन्द की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसके लिए परीक्षा दल एवं प्रेक्षक नियमित भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी 1 घंटे के पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थी अपने साथ स्वयं पानी की बोतल लेकर आये, परीक्षार्थी नाक, मुंह को ढ़ककर एवं सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुये परीक्षार्थी सावधानी बनाये रखें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की जावेगी। इसके लिये जिलाधीश द्वारा प्रत्येक सेन्टर पर स्वास्थ्यकर्मी किट के साथ एक-एक शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। पोरसा विकासखण्ड के 16, अम्बाह के 17, मुरैना के 40, जौरा के 08, कैलारस के 11, पहाडगढ़ के 2 और सबलगढ़ के 10 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने के पक्ष में नहीं संचालक

ऑनलाइन पढ़ाई की पद्धति को अपनाया जाए

संत हिरदाराम नगर (आरएनएन)। संत नगर के शैक्षणिक संस्थाओं के संचालक छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करना है तो केवल बड़ी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए और छोटी कक्षाओं के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून तक अवकाश घोषित कर दिया है। इधर स्कूल संचालकों का कहना है कि 17 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने पर हालातों को देखते हुए निर्णय हो। किस क्लास से स्कूल खोला जाए, इसे लेकर भले ही स्कूल संचालकों की अलग-अलग राय हो लेकिन, उनका मानना है कि बहुत सोच समझकर, व्यापक सुरक्षा सिस्टम जमीन स्तर पर तैयार करने और कड़ी निगरानी के बाद ही स्कूल शुरू किए जाने चाहिए।

दूसरी कक्षा तक रहे बच्चों की छुट्टी

मेरा मानना है एक-दो कमरों में लगने वाले स्कूल तो किसी भी शर्त पर नहीं खुलना चाहिए। कक्षा दूसरी तक भी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना चाहिए। तीसरी क्लास से बच्चों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन कक्षा में बच्चों की संख्या, सैनेटाइजेशन और योग कक्षाएं जरूर लगाई जानी चाहिए। ऑनलाइन पर भी फोकस रहे, लेकिन स्कूल आने की आदत छुटना ठीक नहीं होगा। नवमीं से बारहवीं तक कक्षाएं तीन शिफ्टों में लगाई जानी चाहिए, संक्रमण से बचाव के लिए संख्या और दूरी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

शीला दीदी, शिक्षाविद्

प्राइमरी कक्षाएं बंद रहें पूरे सत्र में

पांचवीं तक बच्चों को स्कूल बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी प्राइमरी स्तर पर पास करने की व्यवस्था है। बच्चों को स्टेडी मटेरियल दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना चाहिए, हालांकि हर विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ई करे यह संभव नहीं है। संसाधनों की कमी से बड़ी संख्या में ऐसे भी स्टूडेंट्सन जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। हायर सेकंडरी स्तर की क्लासें सीमित छात्रों के साथ लगाई जानी चाहिए। पढ़ाई जरूरी है, पर जल्दबाजी कराना भी ठीक नहीं है। **विष्णु गेहानी,** शिक्षाविद्

कोरोनाः सीबीएसई नया पाठ्यक्रम तैयार करेगा

एजेंसी. नई दिल्ली| सीबीएसई कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने से पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने में जुटा है। एक महीने में नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। यह जानकारी सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने शुक्रवार को दी। आहूजा ने कहा, 'हम शिक्षा प्रणाली में अचानक बदलाव नहीं ला सकते। इससे भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। पाठ्यक्रम में सुधार को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। आहूजा 'स्कूलों का भविष्यः कोविड-19 की चुनौतियां और आगे की दिशा' विषय पर अशोक यूनिवर्सिटी की ओर ये आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सीबीएसई अध्यक्ष ने कहा, 'हम पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बना रहे हैं। हमारी योजना मुख्य तत्वों को बनाए रखने की है। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि सीबीएसई पाठ्यक्रम को छोटा करेगा।

परीक्षा केन्द्र सुरक्षित करने की मांग

रीवा |

भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना महामारी के विकराल संक्रमण के बावजूद मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल 10वीं एवं 12वीं परीक्षा आगामी 9 जून से कराने जा रही है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा कराना आवश्यक भी है, लेकिन घोषित परीक्षा केन्द्रों को पूरी संक्रमण मुक्त एवं सुरक्षित कर लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अभी तक जिला प्रशासन एवं शिक्षा मण्डल ने कोई जानकारी नही दी है। जिला प्रशासन से कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सेनिटाइज कराकर परीक्षा तिथि को छात्रों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराएं।

परीक्षा से वंचित छात्रों को फिर से मौका

राज्यपाल ने दिए निर्देश

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर. 29 जून से 30 जुलाई के बीच आयोजित होने जा रहीं स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं से वंचित होने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा। यह निर्देश शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन ने कुलपतियों की बैठक में दिए हैं। रादुविवि के कुलपति प्रो. कपिलदेव मिश्र ने बताया कि बैठक में कहा गया कि परीक्षा के पहले परीक्षा केन्द्रों को सेनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। परीक्षा के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी।

रादुविवि में 8 जून से 33 फीसदी कर्मियों के साथ शुरू होगा काम

- रादुविवि में 8 जून से 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कामकाज की शुरूआत होगी। विवि प्रशासन से जारी आदेश में कहा गया है कि 8 जून से सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कार्यालयों में काम होगा। समस्त विभागाध्यक्षों, प्रभारी अधिकारियों, अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पी-6

जनरल प्रमोशन की माँग को लेकर धरना

- एनएसयूआई ने जनरल प्रमोशन दिए जाने की माँग को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय में धरना दिया। एनएसयूआई के राहुल बघेल, बादल पंजवानी, कपिल भोजक, रघु तिवारी, आसिफ कुरैशी और सक्षम गुलाटी ने कहा है कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी परीक्षाएँ कराई जा रही हैं। जनरल प्रमोशन नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

अगस्त तक बंद रहेंगे सीबीएसई सहित सभी स्कूल

भोपाल। दुनियाभर के तमाम देशों के साथ-साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूलों को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिलहाल बैठक में सभी स्कूलों को अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अगस्त के बाद स्थिति कैसी रहती है उसको देखते हुए ही आगे इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र के अंतर्गत आने वाले सीबीएसई सहित सभी स्कूलों इसका पालन करना होगा।

कोरोना के भय को दूर करने आगे आएं विश्वविद्यालय

भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल लाल जी टंडन ने कहा है कि प्रदेश में आत्मनिर्भर और स्वायत्त विश्वविद्यालय का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। व्यवस्था को मजबूत और सफल बनाने का दायित्व कुलपतियों का है। सर्वोच्च प्राथमिकता अनुशासित, बाधा रहित, भयमुक्त और गाइड लाइंस के अनुसार परीक्षा संचालन को दी जाय। श्री टंडन शनिवार को राजभवन में आयोजित शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे, आयुक्त उच्च शिक्षा मुकेश शुक्ला मौजूद थे।

राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती कठिन दौर है। लेकिन यह नए भारत के निर्माण का अवसर भी है। स्वदेशी नवाचारों के लिए नया वातावरण बना है। शोध, अनुसंधान और नए-नए प्रयोगों के लिए वातावरण निर्माण में विश्वविद्यालय सहयोग करें। कोविड-19 के भय को खत्म करने विश्वविद्यालय आगे आएं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की चेतना को प्रोत्साहन दें। नये स्टार्टअप स्थापना में सहयोग करें। इनके लिए भरपूर राशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में विश्वविद्यालयों में नई सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार हुआ है। एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर और एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म निर्माण के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। कोविड-19 के संबंध में जन जागृति के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा संदेश प्रसारण का जो कार्य किया है, वह सराहनीय है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए कार्य देश-प्रदेश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शक होंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं में सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का

राज्यपाल लालजी टंडन को देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर की कुलपति श्रीमती रेनु जैन ने नैक की ए ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र भेंट किया।

प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है आत्मनिर्भर स्वायत्त विश्वविद्यालय का नया दौर

विशेष ध्यान रखा जाए। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या अथवा क्षमता को बढ़ाकर नियोजित किया जाना चाहिए। परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केन्द्र में आगमन से लेकर परीक्षा समाप्ति बाद वापस जाने तक की समस्त व्यवस्थाओं का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया जाये। तीन पालियों में परीक्षा संचालन को भी परीक्षा अवधि को कम करने अथवा दो पालियों के अंतराल में सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने की आवश्यक व्यवस्थाओं की सभी संभावनाओं पर विचार कर एस.ओ.पी. का निर्माण किया जाए। यह प्रयास किया जाये कि छात्र-छात्राओं को कम से कम यात्रा करनी पड़े। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। दूरस्थ क्षेत्र एवं अन्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वालों के लिए अतिरिक्त परीक्षा की व्यवस्था हो। विद्यार्थियों की काउंसलिंग के भी कार्य किए जाएं। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए नैक ग्रेडिंग की अवधि 6 माह बढ़ाने की अनुमति नैक द्वारा प्रदान कर दी है। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में थर्मल जाँच, सेनिटाइजर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। परीक्षा केन्द्र में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक कक्ष पृथक से आरक्षित रखा जाये। परीक्षार्थी को बुखार आदि के लक्षण मिलने पर उसकी परीक्षा अलग से ली जा सके। बैठक के प्रारंभ में राज्यपाल को इंदौर विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती रेनू जैन ने नैक की ए ग्रेडिंग का प्रमाण तथा जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक भेंट की।

इस अवसर पर सभी कुलपतियों ने परीक्षा संचालन तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गयी। उन्होंने कोविड-19 चुनौती के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के प्रयासों की जानकारी दी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीसुनील कुमार ने सामाजिक दूरी की सुनिश्चितता के लिए स्टुडेंट फ्लो चार्ट बनाकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की जानकारी दी।

आधा दर्जन कलेक्टरों का तबादला कोलसानी आयुक्त ननि भोपाल

भोपाल, (प्रसं)। प्रदेश सरकार ने शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए, जिसके चलते आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर भी प्रभावित हुए हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भोपाल नगर निगम आयुक्त विजय दत्ता को राज्य मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। सिंगरौली कलेक्टर वीएस चौधरी कोलसानी भोपाल नगर निगम आयुक्त होंगे। देवास कलेक्टर श्रीकांत पांडेय को राज्य मंत्रालय में अपर सचिव बना दिया गया है। श्री चंद्रमौली शुक्ला देवास के नए कलेक्टर होंगे। श्री शुक्ला अभी तक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में उप सचिव थे।योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप सचिव आलोक कुमार सिंह धार कलेक्टर होंगे। धार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ को राज्य शासन में उप सचिव बनाया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के संचालक इलैयाराजा टी को रीवा कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। मंडला कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया को राज्य शासन में उप सचिव पदस्थ किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के संचालक वेदप्रकाश नरसिंहपुर कलेक्टर होंगे। नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को राज्य मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग के उप सचिव अनिल कुमार खरे को मंडला कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे को राज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है। आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार को राज्य मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक राजीव रंजन मीना को सिंगरौली कलेक्टर के रूप में और मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव अवधेश शर्मा को आगरमालवा कलेक्टर पदस्थ किया गया है।

इंदौर संभाग के कमिश्नर हटे

भोपाल। राज्य शासन ने शनिवार को इंदौर संभाग के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के स्थान पर पवन कुमार शर्मा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर के आयुक्त को कमिश्नर बनाया गया है। वहीं पूर्व कमिश्नर आकाश त्रिपाठी को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग बनाया गया है।

अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
डॉ. श्रीकांत पांडेय	कलेक्टर, देवास	अपर सचिव,मप्र शासन
आलोक कुमार सिंह	उप सचिव, मप्र शासन	कलेक्टर, धार
इलैयाराजा टी.	संचालक, लघु उद्योग निगम	कलेक्टर, रीवा
श्रीकांत बनोठ	कलेक्टर, धार	उप सचिव, मप्र शासन
जगदीशचंद्र जटिया	कलेक्टर, मंडला	उप सचिव, मप्र शासन
वेदप्रकाश	संचालक, भोपाल गैस त्रासदी	कलेक्टर, नरसिंहपुर
दीपक कुमार सक्सेना	कलेक्टर, नरसिंहपुर	उप सचिव, मप्र शासन
अनिल कुमार खरे	उप सचिव, लोनिवि	कलेक्टर, मंडला
बसंत कुर्रे	कलेक्टर, रीवा	उप सचिव, मप्र शासन
वीएस चौधरी कोलसानी	कलेक्टर, सिंगरौली	आयुक्त नपा निगम भोपाल
बी. विजय दत्ता	आयुक्त, नपा निगम भोपाल	उप सचिव, मप्र शासन
चंद्रमौली शुक्ला	उप सचिव, मप्र शासन	कलेक्टर, देवास
संजय कुमार	कलेक्टर, आगर मालवा	उप सचिव, मप्र शासन
राजीव रंजन मीना	एमडी, ऊर्जा विकास निगम	कलेक्टर, सिंगरौली
अवधेश शर्मा	उप सचिव, सीएम कार्यालय	कलेक्टर, आगर-मालवा

आरजीपीवी ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जारी की गाइडलाइन

भोपाल (आरएनएन)। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 23 जून से होने वाली अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस परीक्षा में जो छात्र किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सकेंगे वे 27 जुलाई से अगली बारी में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। छात्र परीक्षा फीस का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकेंगे। विवि के कुलसचिव प्रो. सुरेश कुशवाह ने बताया कि कुल चालीस हजार छात्रों को परीक्षा देना है। अब तक लगभग 50 फीसदी छात्र परीक्षा फार्म भर चुके हैं।

प्रो. कुशवाह का कहना है विवि छात्रों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए परीक्षा का संचालन दो बार में किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए विवि पूरी तैयारी कर रहा है। विवि द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को परीक्षा केन्द्र पर करीब 50 मिनट पहले पहुंचना होगा। एक कक्ष में 20 छात्र बैठेंगे। वहां प्रत्येक छात्र की स्क्रीनिंग की जाएगी। छात्र के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने पर उन्हें दूसरे कक्ष में बैठाकर परीक्षा देना होगा। बाइक से एक, कार से दो और बस से कुल सीटों की क्षमता से 50 प्रतिशत छात्र ही सवार होकर पहुंच सकेंगे। छात्रों को मास्क पहनने के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र को सेनेटाइज कराया जाएगा लेकिन अपनी सुविधा के लिए छात्रों को सैनिटाइजर साथ लेकर जाने की अनुमति रहेगी। छात्र वर्तमान में जहां रह रहा हैए वहीं के परीक्षा केंद्र को चुन सकेगा। इस परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय से संबंद्ध सभी इंजीनियरिंग, फॉर्मेसी, आर्किटेक्चर एवं एमसीए कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए परीक्षा शुरू होने और समाप्त होने के बाद छात्र कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकेंगे। केंद्र के अंदर भी सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाकर बैठना होगा। परीक्षा देने के बाद छात्रों को सीधे अपने घर जाना होगा।

ट्यूशन फीस छिपाने के लिए निजी स्कूलों ने निकाला स्टॉलमेंट का फॉर्मूला

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर. निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस छिपाने के लिए स्टॉलमेंट का नया फॉर्मूला ईजाद कर लिया है। सेन्ट जोसेफ कॉन्वेन्ट सदर ने फर्स्ट स्टॉलमेंट के तौर पर केजी वन और टू के लिए 4240, पहली से पाँचवीं तक 4480, छठवीं से आठवीं तक 4760, नवमीं और दसवीं तक 4760 और ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए 6600 रुपए जमा करने के लिए मैसेज भेजा है। अभिभावकों का कहना है कि फर्स्ट स्टॉलमेंट से ट्यूशन फीस और अन्य फीस का पता नहीं चल पा रहा है। इसी तरह सेन्ट अलायसियस स्कूल ने भी कक्षा छठवीं से दसवीं तक के छात्रों को 5200 रुपए की फर्स्ट स्टॉलमेंट जमा करने के लिए कहा है। हॉल ही में अभिभावकों ने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ कक्षा नवमीं और दसवीं के छात्रों से फर्स्ट स्टॉलमेंट के रूप में 6600 रुपए जमा कराए जाने की शिकायत की थी।

सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस की ही वसूली की जाएगी। यदि कोई स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस वसूली कर रहा है तो शिकायत उस पर कार्रवाई की जाएगी। - **सुनील नेमा,** डीईओ

अंततः विश्वविद्यालय ने जारी की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियां

यूजी और पीजी के परीक्षा आवेदन 20 जून तक

कार्यालय संवाददाता | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने अंततः विश्वविद्यालयीन सेमेस्टर परीक्षाओं की प्रक्रिया का श्रीगणेश कर दिया है। प्रथम चरण में विश्वविद्यालय ने जून 2020 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के आवेदन की तिथियां घोषित कर दी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जाहिर करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर पद्धति के अनुसार जून 2020 परीक्षा के अन्तर्गत बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रमों के द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम, विधि के द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम सेमेस्टर, बीसीए-बीबीए के द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम सेमेस्टर, बीएएलएलबी द्वितीय, चतुर्थ षष्टम, अष्टम और दशम् सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रम एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमएसडब्ल्यू के द्वितीय, चतुर्थ सेमेस्टर, पीजीडीसीए द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित नियमित, भूतपूर्व और एटीकेटी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र आगामी 20 जून तक भरे जा सकेंगे।

स्नातक एटीकेटी के लिए अंतिम मौका

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना के जरिए कहा है कि स्नातक स्तर बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम सेमेस्टर में एटीकेटी आने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का यह अंतिम मौका है। यही नहीं स्नातक और स्नातकोत्तर के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नहीं जमा किए जाएंगे। सभी को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसके अलावा सभी सेमेस्टरों में मिलकर अधिकतम चार विषयों में एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों को ही परीक्षा आवेदन की पात्रता दी गयी है।

दिसंबर 2019 के एटीकेटी विद्यार्थी भी करेंगे आवेदन

जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित परीक्षा 2019-20 के अन्तर्गत बीए, बीएड, बीएससी, बीएड प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम सेमेस्टर-एटीकेटी दिसंबर 2019 में ऑनलाइन प्रवेशित और एटीकेटी विद्यार्थी भी 20 जून तक परीक्षा आवेदन कर सकेंगे।

29 जून से 31 जुलाई के बीच होंगी परीक्षाएं

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अलग-अलग पाठ्यक्रमों के परीक्षा टाइम-टेबिल घोषित किए जाएंगे। बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि आगामी 29 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

कार्यालय खोलने को लेकर अधिसूचना जारी

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्यालय और विभिन्न विभागों को खोलने संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग, विभागाध्यक्ष, अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति होनी जरूरी है। वहीं 30 से 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति होनी जरूरी है। अध्यापन कार्य फिलहाल स्थगित रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रशासकीय भवन में विद्यार्थियों और आवेदकों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। यही नहीं समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को आरोग्य सेतु अप्लीकेशन का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जो कर्मचारी रोस्टर अनुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, वह उस दिन का कार्य अपने निवास से दूरभाष, वाट्सअप के माध्यम से संपर्क में रहेंगे।

ट्रेजरी एम्पलाई कोड जनरेट करने में विभागीय स्तर पर हो रही हीला हवाली

भा.सं., रीवा | मार्तण्ड क्रमांक 3 में अध्यापक संवर्ग के ट्रेजरी एम्पलाई कोड जनरेट करने में विभागीय स्तर से जमकर हीला हवाली हो रही है। परिणामस्वरूप अब तक करीब दो दर्जन अध्यापकों के ही ट्रेजरी एम्पलाई कोड जनरेट हो पाए हैं। बताया गया है कि मार्तण्ड क्र. 3 संकुल में बीस से पच्चीस अध्यापकों का ही ट्रेजरी एम्पलाई कोड जनरेट किया जा सका है। जबकि ईकेवाईसी संकुल के लगभग सभी अध्यापकों ने पूरी कर ली थी। इस संबंध में बताया गया है कि तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 बाबू की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अध्यापकों की ईकेवाईसी तो पूर्ण कर ली गई थी लेकिन मास्टर डाटा संबंधित लिपिक द्वारा अपग्रेड नहीं करवाया गया था। इस कारण सर्वाधिक अध्यापकों के एम्पलाई कोड जनरेट नहीं किए जा सके। बताया गया है कि इस कार्य में लापरवाही के चलते ही उक्त लिपिक को संकुल मार्तण्ड 3 से अन्यत्र स्थानांतरित करवाया गया था। स्थानांतरण होने के बाद भी अधिकांशतः उक्त लिपिक मार्तण्ड 3 में ही दिखाई देते हैं। अध्यापकों का कहना है कि प्रधानाचार्य को चाहिए कि वर्तमान लिपिकों को हिदायत दें कि कार्य में अवरोध व लापरवाही करने वाले लिपिक को बिना किसी वजह के कक्ष के भीतर प्रवेश न कराया जाय। अध्यापकों का यह भी कहना है कि अध्यापकों का प्रभार वर्तमान में जिस लिपिक को सौंपा गया है वह कार्य में इतने निपुण नहीं हैं और मजबूरीवश पुराने लिपिक को बुलाया जाता है। जो स्थानांतरित होने के कारण कार्य में गड़बड़ी करते हैं। परिणामस्वरूप अध्यापक कहीं न कहीं किसी तरह का शिकार हो रहे हैं। संकुल प्राचार्यों से आग्रह किया गया है कि जब तक कार्य में पारंगत लिपिक की पदस्थापना संकुल में नहीं होती तब तक कुछ चिन्हित अध्यापकों की टीम को उक्त कार्य के लिए आदेशित किया जाय ताकि समयावधि में अध्यापकों का सातवां वेतनमान एवं एम्पलाई कोड की प्रक्रिया पूर्ण हो सके ताकि मई माह का वेतन दिया जा सके।

संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने मंत्री डॉ. मिश्रा को सौंपा ज्ञापन

दतिया ब्यूरो

अतिथि शिक्षकों को मई व जून का मानदेय दिलाने एवं उनका सेवाकाल 12 माह का किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गजेन्द्र राजपूत के नेतृत्व में शनिवार को म.प्र. शासन के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया है कि अतिथि शिक्षक 12 माह से अल्प वेतनमान पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उन्हें शैक्षक्षिक सत्र प्रारंभ होने पर रख जाता है और सत्र समाप्त होने पर हटा दिया जाता है। अतिथि शिक्षक वर्तमान में कोविड-19 के समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अतः अतिथि शिक्षकों का सेवाकाल 12 माह का किया जाए। सभी अतिथि शिक्षक वर्तमान वेतनमान पर ही कार्य करने को तैयार हैं। डॉ. मिश्रा मंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में राधेलाल अहिरवार, धीरज शर्मा, इरशाद शाह, अंशु यादव, प्रवीण लोधी, मुरारीलाल, संतोष अहिरवार, अटल रावत, दिवाकर तिवारी, मुकेश बघेल, सुनील प्रजापति, अर्जुन कुशवाह, अर्जुन सिंह निरंजन, शैलेन्द्र सिंह सेंगर, कौशल दोहरे, रमाकांत श्रीवास्तव शामिल थे।

मंत्री डॉ. मिश्रा को ज्ञापन सौंपते अतिथि शिक्षक।

हिंदी विवि से निकाले गए गेस्ट फैकल्टी ने तनाव में आकर काटी हाथ की नस, मौत

बाथरूम में मिली लाश

भोज विवि अधिकारी आवास चूनाभट्टी इलाके की घटना

हमारे संवाददाता, भोपाल

अटल बिहारी बाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से निकाले गए एक गेस्ट फैकल्टी ने तनाव में आकर चाकू से हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली। उसकी घर के बाथरूम में लाश मिली है। बताया गया है कि खून अधिक बह जाने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वह भोज विवि में अपनी मौसी के घर में रहता था और बीए की पढ़ाई भी कर रहा था। चूनाभट्टी पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

थाना प्रभारी ऋचा जैन (प्रशिक्षु डीएसपी) के मुताबिक 21 वर्षीय आर्यन सिंह पिता मनोहर सिंह यहां भोज विवि के अधिकारी आवास में अपनी मौसी डा. हेमलता दिनकर के साथ रहता था। शुक्रवार रात खाना खाने के बाद आर्यन सोने के लिए चला गया था। शनिवार सुबह करीब नौ बजे दूध वाले ने घंटी बजाई। इस पर हेमलता ने दूध लिया। जबकि रोजाना आर्यन ही दूध

लेता था। इसके बाद मौसी ने देखा तो आर्यन बाथरूम में मृत हालत में पड़ा था। उसके बाएं हाथ की नस कटी थी और पास में खून से सना चाकू व बाथरूम के चारों ओर खून पड़ा था। चीख-पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी जैन का कहना है कि पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

मां की मौत के बाद पिता ने कर ली थी दूसरी शादी

भोज विवि में प्रोफेसर डा. हेमलता ने पुलिस को बताया कि जब आर्यन दो साल का था, तब उसकी मां की मौत हो गई थी। इसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से आर्यन नाना-नानी और उनके साथ रहा है। आर्यन इन दिनों बीए की पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम अटल बिहारी बाजपेयी हिंदी विवि में गेस्ट फैकल्टी था। लॉकडाउन की वजह से बीती एक जून को आर्यन समेत कुछ अन्य लोगों को हिंदी विवि से निकाल दिया गया। तब से आर्यन तनाव में था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों की मानें शुक्रवार को हिंदी विवि के कुलपति रामदेव भारद्वाज ने आर्यन को अपने घर बुलाया था। जहां उसकी नौकरी से निकालने को लेकर कुलपति के साथ बहस हुई थी। इसके बाद कुलपति ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। आर्यन लेखा शाखा में काम करता था।

नवमीं-ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को मिली रि-टोटलिंग की सुविधा

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय ने नवमीं-ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को रि-टोटलिंग की सुविधा दी है। रि-टोटलिंग के लिए आवेदन स्कूल स्तर पर किए जा सकेंगे। स्कूल स्तर पर ही रि-टोटलिंग के सभी प्रकरणों का निराकरण तीस जून तक किया जाएगा। हालांकि विभाग ने स्कूलों की तीस जून तक छुट्टी घोषित कर दी है। जिससे रि-टोटलिंग के प्रकरणों के निराकरण को लेकर असमंजस बना हुआ है।

जेडी आफिस की छत का प्लास्टर गिरा, बच गए कर्मचारी, अधिकारी

जर्जर है भवन, अब तक नहीं हुआ भवन का मरम्मत

जागरण, रीवा। जेडी लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय में बड़ा हादसा टल गया। शनिवार की दोपहर को अचानक छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। छत के नीचे कुछ कर्मचारी खड़े थे, जिन्हें प्लास्टर छूते हुए फर्स पर जा गिरी। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। यदि भवन को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा हादसा तय है।

ज्ञात हो कि मार्तण्ड स्कूल परिसर में ही लोक शिक्षण संचालनालय का संयुक्त संचालक कार्यालय संचालित हो रहा है। भवन लंबे समय से जर्जर है। हर साल बारिश में यहां छत का प्लास्टर भराभरा कर गिरता है। इस साल भी पहली ही बारिश में इस तरह का हादसा हुआ है। गुरुवार की बारिश से भवन पूरी तरह से तर हो गया था। शनिवार को तेज धूप से छत सूखते ही प्लास्टर कमजोर हुआ और दोपहर में एक बड़ा

हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया। इस दौरान कार्यालय में कर्मचारी मौजूद रहे। इन कर्मचारियों को छूते हुए प्लास्टर फर्स पर गिरा। इस घटना में कुछ लोगों के हाथ और पैर में चोटे भी आई। हालांकि बड़ी घटना टल गई। कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। आए दिन यहां इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन भवन मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। शायद प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है।

पूरी छत टपकती है

जेडी लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर है। यह भवन सभी जगह से टपकता है। बारिश में यहां कर्मचारियों का काम करना तक मुश्किल हो जाता है। दस्तावेज और कम्प्यूटर तक प्रभावित होत हैं। कई दस्तावेज बारिश में पानी के रिसाव के कारण खराब भी हो चुके हैं।

बारिश के पानी और गंदगी से कर्मचारी परेशान, कमिश्नर से लगाई गुहार

रीवा। जेडी लोक शिक्षण संचालनालय के कर्मचारियों ने कमिश्नर रीवा संभाग से गुहार लगाई है। परिसर में व्याप्त गंदगी और गंदे पानी के बहाव से कार्यालय में काम करना मुश्किल हो गया है। पूरा परिसर दुर्गंध मार रहा है। इससे निराज दिलाने की मांग कमिश्नर से की गई है। ज्ञात हो कि मार्तण्ड स्कूल के मैदान को ही प्रवासी मजदूरों के लिए शिविर स्थल बनाया गया था। यहां प्रवासी मजदूर जो कचरा छोड़कर गए थे, उसका उठाव नहीं हुआ। इसके अलावा सेंट्रल किचन और छात्रावास का गंदा पानी भी परिसर में ही बहकर आता है। कलेक्ट्रेट के बारिश का पानी भी कार्यालय के पास जमा होता है। इससे जेडी कार्यालय परिसर में गंदगी का अंबार लग गया है। कूड़ा कचरा तो पहले से ही डंप था। अब गंदा पानी भी यहीं आकर रुक रहा है। ऐसे में कार्यालय परिसर में दुर्गंध फैल रही है। कर्मचारियों का कार्यालय में बैठकर काम करना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि सभी कर्मचारियों ने कमिश्नर को पत्र सौंप कर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाई जाए वर्ना कर्मचारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे।

नए भवन का निर्माण रुका

जेडी लोक शिक्षण संचालनालय के नए भवन के लिए भी शासन से बजट जारी हो चुका है। भवन निर्माण भी शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले एक साल से काम बंद है। गवर्नमेंट स्कूल कमांक एक के पीछे नया भवन बन रहा है। समय पर काम न होने के कारण कार्यालय शिफ्ट नहीं हो पा रहा है।

सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का मामला

सालभर बाद भी शिक्षक नियुक्त नहीं, परीक्षा से पहले छिपाए पद

मेरी नौकरी

इंदौर • डीबी स्टार

प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग दो साल पहले परीक्षा ले चुका है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों को नौकरी आज तक नहीं मिली है। मई 2018 में परीक्षा होने के बाद विभाग ने महीनेभर में रिजल्ट जारी करने और तीन महीने में नियुक्ति घोषित करने का दावा किया था। लंबी जद्दोजहद के बाद सितंबर 2019 में मेरिट लिस्ट जारी की। तब प्रतिभागियों में उम्मीद जागी थी कि जल्द नौकरी मिल जाएगी। इस बात को भी नौ महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक प्रतिभागी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं, जबकि इस बीच सरकारें तक बदल गईं। करीब दो साल पहले विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने इंदौर में संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले युवक और युवतियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर वादा किया था कि चुनाव होते ही नियुक्ति दी जाएगी। इसके फोटो-वीडियो डीबी स्टार के पास उपलब्ध हैं। इसके बावजूद आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग की लेटलतीफी से त्रस्त प्रतिभागी अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

परीक्षा के बाद पद 60 हजार 686 से घटाकर 5670 किए

स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा से पहले यह नहीं बताया कि किस विषय के कितने पद भरे जाएंगे। रिक्त पदों की सूची जरूर जारी हुई थी। हिंदी, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों से लाखों आवेदकों ने अप्लाय किया था। 2018 में जारी राजपत्र में वर्ग-2 के 60 हजार 686 पद रिक्त बताए थे, लेकिन भर्ती के समय 5670 पद ही घोषित किए गए। इस तरह पदों की संख्या 10 गुना से भी कम होने से परीक्षार्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

दो साल पहले इंदौर में सीएम बोले थे: जल्द देंगे नियुक्त

2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रतिभागियों से मिले थे। तब उन्होंने जल्द नियुक्ति देने का भरोसा दिलाया था। उनके साथ सेल्फी भी ली थी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी पालन नहीं करने का आरोप

मध्यप्रदेश युवा शिक्षित बेरोजगार मंच पास अभ्यर्थी की इंदौर संयोजक ममता निगम ने बताया कि शिक्षक भर्ती में आरटीई के नियम का पालन किया जाना चाहिए। यानी हर विषय के लगभग समान पद निकाले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में बिहार में हुई भर्ती परीक्षा में साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और अन्य विषयों के 5425 पद रखे गए। प्रदेश में इन विषयों के क्रमशः 50, 60 और 100 पद ही रखे गए।

उर्दू के केवल 18 पद सृजित किए। यानी इन विषयों का एक जिले में केवल एक शिक्षक भर्ती हो पाएगा। क्या एक शिक्षक की कमी के लिए परीक्षा ली जाना चाहिए? जिले में यह कमी तो अतिथि शिक्षक से भी पूरी हो सकती थी, जबकि कुल 5670 में से अकेले अंग्रेजी के आधे से भी अधिक 3358 पद रखे गए हैं। इसी तरह गणित के 1312 तो संस्कृत के 772 पद तय किए गए हैं। कायदे से गणित और विज्ञान के पद अधिक होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन्हीं विषयों में कमजोर होते हैं।

सात लाख ने दी थी परीक्षा, फीस से सरकार को मिले 35 करोड़

प्रदेशभर के करीब सात लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया था। सामान्य श्रेणी के आवेदकों की फीस 700 रुपए थी जबकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों ने 350 रुपए फीस चुकाई थी। यदि दोनों श्रेणियों का एवरेज प्रति उम्मीदवार 500 रुपए भी निकाला जाए तो केवल परीक्षा फीस से ही सरकार को 35 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। सात लाख में से नौकरी केवल 5670 उम्मीदवारों को ही मिलेगी।

प्रक्रिया 29 जून से शुरू करेंगे

विभिन्न कारणों से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबित हो गई थी। 29 जून से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण, सुधार और संशोधन कार्य किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को जुलाई तक नियुक्ति देने की उम्मीद है। शिक्षकों के पद बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा विभाग ने जरूरत के आधार पर विषयवार पद निकाले हैं।

गौतम सिंह, निदेशक, लोक शिक्षण संचालनालय

अंग्रेजी के लिए 6629 क्वालिफाइड, जबकि पद केवल 3358

अंग्रेजी विषय के लिए 6629 प्रतिभागियों ने क्वालिफाई किया है और हर दूसरे प्रतिभागी की नौकरी पक्की है, क्योंकि इसके 3358 पद निकाले गए हैं। वहीं, सामाजिक विज्ञान में 61269, हिंदी में 56327, विज्ञान में 41699 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन इन विषयों के पदों की कुल संख्या 210 है। यानी 1,59,295 मेरिट वालों में से 1,59,085 बेरोजगार ही रह जाएंगे। गणित विषय के भी 38024 प्रतिभागी क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन नौकरी केवल 1312 को ही मिल सकेगी, जबकि प्रदेश के स्कूलों में उक्त विषयों के 35 हजार से अधिक पद रिक्त हैं।

अलग-अलग जारी होगा कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

सागर| इस साल लॉकडाउन के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर स्थगित हुए थे। कक्षा 10वीं की स्थगित दो विषयों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वहीं कक्षा 12वीं के स्थगित पेपर की परीक्षा 9 जून से शुरू हो रही है। दसवीं की कॉपियों का मूल्यांकन भी लगभग पूरा होने पूरा हो चुका है। जून के दूसरे हफ्ते में कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित करने के संकेत दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव अनिल सुचारी का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जून के दूसरे हफ्ते यानी 14 से 15 जून तक कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कक्षा 12वीं का रिजल्ट जुलाई माह में घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दोनों कक्षाओं का रिजल्ट अलग-अलग जारी किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में एक महीने या 15 दिन का अंतर रहेगा।

शिक्षिका ने रंगोली के माध्यम से छात्राओं को दिया संदेश

खंडवा | महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उमावि की व्याख्याता संगीता सोनवाने ने कोरोना से बचाव का संदेश रंगोली बनाकर छात्राओं को दिया। रंगोली में बताया कि छात्राएं परीक्षा देने जाएं तो मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस रखें, स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए दूध में हल्दी डालकर पीएं, घर में बार-बार अपने हाथ को साबुन से धोएं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भी दिनभर मास्क पहनने व हाथों को सैनेटाइज्ड करना जरूरी है।

संदला के प्राचार्य दुबे को दिया डीईओ का प्रभार

धार | जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार संदला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य दिनेश दुबे को दिया गया है। वर्तमान अधिकारी मंगलेश व्यास को इस दायित्व से मुक्त किया गया है। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने कार्य सुविधा की दृष्टी से इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं। दुबे अपने दायित्वों के अलावा डीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे।

12वीं बोर्ड परीक्षा 9 जून से • कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले छात्र भी हो सकेंगे शामिल, हर परीक्षा केंद्र पर होगा आइसोलेशन रूम

जिस छात्र का ज्यादा तापमान, वह आइसोलेशन रूम में देगा बोर्ड परीक्षा

12वीं के बाकी पेपर के लिए 16 जून तक चलेगी परीक्षा, जिले में 131 केंद्र बनाए हैं

इंदौर/भोपाल • **डीबी स्टार**

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने पर छात्र को आइसोलेशन रूम में बैठाकर परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए हर केंद्र पर आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि 12 की बोर्ड परीक्षा 9 से 16 जून तक चलेगी। डीईओ राजेंद्र मकवानी ने बताया कि 12वीं की परीक्षा के शेष पेपरों के लिए जिले में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिले में निर्धारित उप केंद्र पर शामिल छात्रों के प्रवेश-पत्र मूल परीक्षा केन्द्र के नाम से ही जारी किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक आइसोलेशन कक्ष भी होगा जहां अधिक तापमान वाले या कोरोना के लक्षण वाले छात्र परीक्षा दे सकेंगे।

नौ हजार छात्रों ने केंद्र बदलने का आवेदन दिया

प्रदेशभर में 9 हजार छात्रों ने केंद्र बदलने के लिए मंडल को आवेदन दिया है। प्रदेशभर में 3500 परीक्षा केंद्र हैं। 12वीं की परीक्षा में 8.50 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षा की समीक्षा को लेकर स्कूल विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी सभी डीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा चुकी है।

परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होगी

कोरोना से बचाव के साधन और जरूरत पड़ने पर परीक्षार्थियों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र बदलने पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए मंडल संभागीय मुख्यालयों को 4-4 लाख और जिलों को 3-3 लाख का अतिरिक्त भुगतान करेगा।

शिक्षकों को कोरोना सर्व से मुक्त किया

परीक्षा के मद्देनजर कोरोना सर्वे एवं टीकाकरण में जुटे शिक्षकों को 5 से 18 जून तक मुक्त कर दिया है। 18 तारीख बाद ये शिक्षक पुनः सर्वे एवं टीकाकरण में लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षक इस संबंध में संबंधित एसडीएम को अपनी जानकारी देंगे।

डीईओ को आवेदन कर केंद्र बदल सकते हैं छात्र

किसी भी छात्र या उसके परिजन को क्वारेंटाइन किया है या जो छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें छोड़कर कंटेनमेंट क्षेत्र के अन्य सभी छात्र 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे। इन्हें मंडल द्वारा जारी प्रवेश पत्र के आधार पर बिना रोक-टोक के कंटेनमेंट एरिया से परीक्षा केंद्र तक आने-जाने की मंजूरी दी गई है। कोई छात्र अपने निवास स्थान पर नहीं है और वह अब भी वर्तमान लोकेशन पर स्थित किसी केंद्र पर परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसे जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना होगा। क्योंकि कई छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे। बाद में इसकी जानकारी मंडल को उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षार्थी को सर्दी- जुकाम तो कोरोना टेस्ट की सलाह दें

12वीं की परीक्षा को लेकर मंडल के सचिव अनिल सुचारी ने शुक्रवार को सभी कलेक्टरों, एसपी, जिला पंचायतों के सीईओ समेत विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाए। स्क्रीनिंग के दौरान परीक्षार्थी का तापमान अधिक होने या फिर सर्दी- जुकाम के लक्षण पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन कक्ष में बिठाया जाए। पेपर देने के बाद परीक्षार्थी को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह भी दी जाए। बोर्ड द्वारा पहले ही हर परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन कक्ष बनाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

एटीकेटी व बीएबीएड के छात्र 20 तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म

रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक एटीकेटी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जारी किए हैं। स्नातक अंतिम अवसर के रूप में एटीकेटी परीक्षा में बैठने के पात्र छात्र 20 जून तक ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम सहित अन्य स्नातक सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के छात्र विलम्ब शुल्क के साथ 26 जून तक परीक्षा फार्म भर पायेंगे। विश्वविद्यालय ने सूचना में सिर्फ ऑनलाइन फार्म ही स्वीकार करने के लिए कहा है। इसके अलावा 20 जून तक नियमित बीएबीएड व बीएससी बीएड के छात्रों को भी ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने विश्वविद्यालय ने निर्देशित किया है।

बीयू का छात्र डीएवी के परीक्षा सेंटर में भी दे सकेगा एग्जाम छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय बना रहे ऐसी व्यवस्था

परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर राजभवन में हुई कुलपतियों की बैठक राज्यपाल लालजी टंडन ने दिए परीक्षाओं को लेकर दिशा-निर्देश

नगर संवाददाता, भोपाल

कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के यूजी-पीजी छात्रों के एग्जाम होना हैं। इसकी तैयारी सभी विश्वविद्यालयों ने कर ली है। परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा को लेकर शनिवार को राजभवन में कुलपतियों की बैठक हुई। बैठक में कुलपतियों ने परीक्षा की तैयारियों की जानकारी राजभवन को दी। राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यपाल ने परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए। प्रदेश के सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल किए जाने के लिए विश्वविद्यालयों ने अलग व्यवस्था बनाए जाने की जानकारी भी राजभवन में दी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से छात्र अपने घर चले गए हैं। अगर छात्र परीक्षा के समय संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा सेंटर पर नहीं आ पाते हैं, तो वे दूसरे विश्वविद्यालय के परीक्षा सेंटर पर भी एग्जाम दे सकेंगे। ऐसी व्यवस्था विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। इससे अगर बीयू का छात्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र से एग्जाम देना चाहें तो वह दे सकता है। बैठक में राज्यपाल लाल जी टंडन ने कहा है कि प्रदेश में आत्म निर्भर और स्वायत्त विश्वविद्यालय का नया दौर प्रारम्भ हो रहा है। व्यवस्था को मजबूत और सफल बनाने का दायित्व कुलपतियों का है। सर्वोच्च प्राथमिकता अनुशासित, बाधा रहित, भयमुक्त और गाइड लाइंस के अनुसार परीक्षा संचालन को दी जाए।

तीन पालियों में कराएं एग्जाम

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं में सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या अथवा क्षमता को बढ़ाकर नियोजित किया जाना चाहिए। तीन पालियों में परीक्षा संचालन को भी परीक्षा अवधि को कम करने अथवा दो पालियों के अंतराल में सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने की आवश्यक व्यवस्थाओं की सभी संभावनाओं पर विचार कर एसओपी का निर्माण किया जाए।

नैक ग्रेडिंग के लिए मिला छह महीने का समय

राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए नैक ग्रेडिंग की अवधि 6 माह बढ़ाने की अनुमति नैक द्वारा प्रदान कर दी है। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में थर्मल जांच, सेनिटाइजर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। परीक्षा केन्द्र में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक कक्ष पृथक से आरक्षित रखा जाए। परीक्षार्थी को बुखार आदि के लक्षण मिलने पर उसकी परीक्षा अलग से ली जा सके।

कोरोना से हो गई ओएसडी की मौत राजभवन में चलती रही बैठक

कोरोना संक्रमण से शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ एक ओएसडी की मौत हो गई। वे इससे पहले हिंदी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार भी रहे थे। वे कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद चिरायु अस्पताल में भर्ती हो गए थे। शनिवार को अचानक उनकी मौत हो गई। इधर राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक चलती रही। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कुलपतियों को ओएसडी की मौत की खबर तक नहीं लगी। बैठक के बाद कुलपतियों और अधिकारियों का लंच भी राजभवन में हो गया। राजभवन से बाहर निकलने के बाद कुलपतियों और अधिकारियों को ओएसडी की मौत की जानकारी मिल पाई।

परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना होगा अनिवार्य:कलेक्टर

रीवा(नव स्वदेश)। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी तथा व्यवसायिक परीक्षा के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9 जून से 16 जून तक जिले के 99 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इस संबंध कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कहा है कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षार्थी मास्क पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में आये। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल गन से स्क्रीनिंग की जायेगी। इस लिए परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पूर्व सभी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हो जायें। कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्र अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा प्रारंभ होने तथा समाप्त होने के बाद सेनेटाइज करायें। इसके लिए शहरी क्षेत्र में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यवस्था करेंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों में कम से कम 50 मास्क तथा थर्मल स्क्रीनिंग गन अनिवार्य रूप से व्यवस्था करायें। सभी परीक्षा केन्द्रों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल तैनात रहेंगे। सभी केन्द्राध्यक्ष, राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए बोर्ड परीक्षा आयोजित करें। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों का वितरण किया जा रहा है। सभी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर लें।

कंटेनमेंट एरिया के कारण बोर्ड परीक्षा के चार केन्द्रों में स्थान परिवर्तन

रीवा(नव स्वदेश)। कोरोना संक्रमण के कारण जिले की कुछ बस्तियों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है जिसके कारण यहां आवागमन प्रतिबंधित है। कंटेनमेंट क्षेत्र में होने के कारण 9 जून से आरंभ हो रही बोर्ड परीक्षा के चार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी रामनरेश पटेल ने बताया कि शा.उ.मा.वि. गोड़हर (321114) के परीक्षा केन्द्र को उमादत्त उ.मा.वि. ढेकहा (322368) में बनाया गया है। शा. ज्ञानोदय आवासीय अनुसूचित जाति, जनजाति उ.मा.वि. झिरिया रीवा (321130) के परीक्षा केन्द्र को सेन्ट्रल एकेडमी उ.मा.वि. कालेज चौराहा रीवा (सीबीएसी) में बनाया गया है। शा.उ.मा.वि. कटरा (321070) के परीक्षा केन्द्र को अब शा. हाईस्कूल जमुई (321150) में बनाया गया है। शा.उ.मा.वि. खजुहा (321077) के परीक्षा केन्द्र को शा.उ.मा.वि. लक्ष्मणपुर (321142) में बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों को भी इस संबंध में सूचना देने के निर्देश केन्द्राध्यक्षों को दिए हैं।

विद्यार्थियों की फीस सरकार ने जमा की

भोपाल। मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 27 हजार 281 विद्यार्थियों की 18 करोड़ 88 लाख 24 हजार रुपए की फीस सरकार ने जमा करवाई है। यह योजना मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शुरू की थी। योजना अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा के 1500 विद्यार्थियों की एक करोड़ 88 लाख 97 हजार 321, आईआईटी, एनआटी के 2 विद्यार्थियों की एक लाख 78 हजार 700, क्लैट-एनएलआईयू के 9 विद्यार्थियों की 19 लाख 55 हजार 500, मेडिकल (नीट) में 19 विद्यार्थियों की एक करोड़ 70 लाख 77 हजार, उच्च शिक्षा में 23 हजार 896 विद्यार्थियों की फीस सरकार द्वारा जमा करवाई गई है।

कंटेनमेंट एरिया के कारण बोर्ड परीक्षा के चार केन्द्रों में स्थान परिवर्तन

रीवा|कोरोना संक्रमण के कारण जिले की कुछ बस्तियों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है जिसके कारण यहां आवागमन प्रतिबंधित है। कंटेनमेंट क्षेत्र में होने के कारण 9 जून से आरंभ हो रही बोर्ड परीक्षा के चार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी रामनरेश पटेल ने बताया कि शा.उ.मा.वि. गोड़हर (321114) के परीक्षा केन्द्र को उमादत्त उ.मा. वि. ढेकहा (322368) में बनाया गया है। शा. ज्ञानोदय आवासीय अनुसूचित जाति, जनजाति उ.मा.वि. झिरिया रीवा (321130) के परीक्षा केन्द्र को सेन्ट्रल एकेडमी उ.मा.वि. कालेज चौराहा रीवा (सीबीएसी) में बनाया गया है। शा.उ.मा.वि. कटरा (321070) के परीक्षा केन्द्र को अब शा. हाईस्कूल जमुई (321150) में बनाया गया है। शा.उ.मा.वि. खजुहा (321077) के परीक्षा केन्द्र को शा.उ.मा.वि. लक्ष्मणपुर (321142) में बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों को भी इस संबंध में सूचना देने के निर्देश केन्द्राध्यक्षों को दिए हैं। **बोर्ड परीक्षा के सभी परीक्षार्थी मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर आयें-** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी तथा व्यवसायिक परीक्षा के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9 जून से 16 जून तक जिले के 99 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी।

सूचना

आम सभा-2020

आंध्रः ठेले पर केले बेचने को मजबूर हुआ शिक्षक

हैदराबाद | जिस शिक्षक पर देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, उसे मजबूर होकर ठेले पर केले बेचने पड़ रहे है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में रहने वाले वेंकटसुब्बया की, जो एक निजी स्कूल में तेलुगु शिक्षक के रूप में 2008 से कार्यरत थे। वेंकटसुब्बया राजनीति विज्ञान और तेलुगू भाषा में एमए और बीएड की पढ़ाई कर चुके हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने और नए छात्र नहीं जोड़ पाने पर स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर ठेले पर केले बेचने पड़ रहे हैं।

राज्यपाल ने बैठक में ली विश्वविद्यालय परीक्षाओं की जानकारी

बुखार होने पर अलग कमरे में बैठकर परीक्षा देंगे स्टूडेंट, हर पाली में होगा सेनिटाइजेशन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजभवन में शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक में शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन ने परीक्षाओं की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में कुलपतियों से परीक्षा केंद्र में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक कक्ष पृथक से आरक्षित रखने को कहा गया है। इन अतिरिक्त कमरों में परीक्षार्थी को बुखार आदि के लक्षण मिलने पर उसकी परीक्षा अलग से ली जाएगी। परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं में सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई।

राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केंद्र में आगमन से लेकर परीक्षा समाप्ति बाद वापस जाने तक की समस्त व्यवस्थाओं का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया जाए। तीन पालियों में परीक्षा संचालन को भी परीक्षा अवधि को कम करने अथवा दो पालियों के अंतराल में सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने की आवश्यक व्यवस्थाओं की सभी संभावनाओं पर विचार कर एसओपी का निर्माण किया जाए। यह प्रयास किया जाए कि छात्र-छात्राओं को कम से कम यात्रा करनी पड़े। दूरस्थ क्षेत्र एवं अन्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वालों के लिए अतिरिक्त परीक्षा की व्यवस्था हो। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे, आयुक्त उच्च शिक्षा मुकेश शुक्ला मौजूद थे।

खास बातें

- आकस्मिक परिस्थितियों के लिए एक कक्ष आरक्षित रहेगा
- दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त परीक्षा की व्यवस्था होगी

राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन मे विवि के कुलपतियों से चर्चा करते हुए।

कोविड-19 के भय को खत्म करने विवि आगे आएं: राज्यपाल

राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि प्रदेश में आत्म निर्भर और स्वायत्त विश्वविद्यालय का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। व्यवस्था को मजबूत और सफल बनाने का दायित्व कुलपतियों का है। कोविड-19 की चुनौती कठिन दौर है, लेकिन यह नए भारत के निर्माण का अवसर भी है। कोविड-19 के भय को खत्म करने विश्वविद्यालय आगे आएं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की चेतना को प्रोत्साहन दें। नए स्टार्टअप के स्थापना में सहयोग करें। इनके लिए भरपूर राशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में विश्वविद्यालयों में नई सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रदेश के विवि द्वारा किए गए कार्य देश-प्रदेश की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शक होंगे।

नैक ग्रेडिंग की अवधि 6 महीने बढ़ी

राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए नैक ग्रेडिंग की अवधि 6 माह बढ़ाने की अनुमति नैक द्वारा प्रदान कर दी है। बैठक के प्रारम्भ में राज्यपाल को इंदौर विश्वविद्यालय की कुलपति रेनू जैन ने नैक की 'ए' ग्रेडिंग का प्रमाण तथा जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक भेंट की। इस अवसर पर सभी कुलपतियों ने परीक्षा संचालन तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गयी। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार ने सामाजिक दूरी की सुनिश्चितता के लिए स्टूडेंट फ्लो चार्ट बनाकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की जानकारी दी।

राजभवन के बाहर खड़े होकर एनएसयूआई ने परीक्षा के निर्णय पर जताया विरोध

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं का विरोध जताया और राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि परीक्षा करवाने का निर्णय गलत है, इससे प्रदेश के लाखों छात्रों की जान खतरे में आ सकती है। ऐसे में अगर परीक्षा कराई जाती है तो लाखों छात्र-छात्राओं को कोरोना संक्रमण फैलने का अत्यधिक डर रहेगा जिससे कि वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त होंगे। जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि यह परीक्षा करवाने का उचित समय नहीं है।